when domestic profits are high, manufacturers will have no incentive to export. The only way to encourage exports, and this is accepted world-wide, is to make export production and export activity more profitable than domestic profits. I think the system of incentives and the package that we have worked out as a policy, encourages export production and exports because today I believe export profits are good, and the answer is to make export activity more profitable so that people will export more even if it means compression of some domestic demand.

MR. CHAIRMAN: Question 362.

India's talks with the President of Asian Development Bank

*362. **DR. RATNAKAR PANDEY**:[†]
SHRI BEKAL UTSAHI:

Will the Minsiter of FINANCE be pleased to state:

(a) whether during his recent visit to Bangkok he met the President of the Asian Development Bank, to impress upon him to increase the ADB's exposure to India; and

(b) if so, what was the response thereto, indicating the likely aid to India?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) and (b). Yes. In the meeting with the President of Asian Development Bank at Bangkok, the current lending programme and the modalities to, increase ADB's exposure to India specially the quick disbursing component was discussed. ADB's response was positive.

डा० रत्नाकर पाण्डेय: माननीय सभापति जी, जब यह सरकार सत्ता में आई थी तो उस समय अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य बैंकों से ऋण मिलना बंद हो गया था और विदेशी मुद्रा का भंडार भी नहीं के बराबर था। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय ऋण को चुकता करने में दिवालिये की स्थिति में देश था। अब जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि उस समय 26 करोड़ रुपये यानी 1.3 मिलियन डालर थी, वह आज 8 हजार करोड़ ....(**व्यवधान**)। जो उपलब्धियां है वे बतानी पड़ेंगी क्योंकि प्रश्न विश्व बैंक से पैसे लेने का है। यह अब 8 हजार करोड़ और 3.1 मिलियन डालर हो गया है। चार सौ मिलियन डालर का सोना विदेशों में था, वह अब लौट कर आ गया है। उसके अतिरिक्त दो सौ मिलियन डालर का सोना स्टेट बैंक व्यवसाय में ले रहा है। पहले एन०आर०आई० 335 मिलियन डालर बराबर प्रति माह निकाल रहे थे, आज वह सारा कुछ रूक गया है विश्व बैंक में और बैंकिग संस्थानों में और दुनिया में हमारी क्रेडिट बनी है। वाणिज्यिक उधार की स्थिति में मजबूती आई है, हमारी साख बनी है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि देश को जिस आर्थिक संकट का सामना इन सब के बावजूद आज भी करना पड़ रहा है और उसे विश्व बैंक के एक अवलोकन के अनुसार अवमूल्यन से पहले 1 लाख 82 हजार करोड़ के विदेशी मुद्रा के ऋण का भुगतान करना था तो इस नाजुक आर्थिक स्थिति को देखते हुए देश को आर्थिक संकट से उभारने के लिए एशियाई विकास बैंक से किस प्रकार की और कितनी सहायता मिलने के आसार हैं? क्या इस बारे में कोई लिखित रूप से आश्वासन सरकार को प्राप्त हुआ है? इसके पहले एशियाई विकास बैंक से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त होती थी और उसकी शर्तें क्या थी? क्या एशियाई विकास बैंक ने आर्थिक सहायता के लिये किसी प्रकार की शर्त आपके सामने रखी है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, यह मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं?

श्री रामेश्वर ठाकुर: सभापति महोदय, एशियन डेवलपमेंट बैंक एक अन्तरराष्ट्रीय बैंक है जिसके साथ भारत का संबंध प्रारंभ से ही जुड़ा हुआ है। पिछले 25 वर्षों की अवधि में 1986 ईसवी तक हमने अधिकार होते हुए भी एशियन डेवलपमेंट बैंक से कोई उधार या किसी प्रकार का कर्ज नहीं लिया। उसके बाद से पिछले वर्षों में हमें आधारभूत योजनाओं के लिये कई ऋण मिले हैं और कई ऋण अभी वार्तालाप की स्थिति में हैं। हमें चालू वर्ष में जिन ऋणों की स्वीकृति हुई है उसका विवरण मैं तत्काल दे रहा हूं। इसमें इमरजेंसी असिस्टेंस लोन गल्फ क्राइसेस के लिये 150 मिलियन डालर है। सेंकड रेलवे के लिये 225 मिलियन डालर है, गांधार आयल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजक्ट के लिये 267.30 पिलियन डालर है, हाइड्रो कार्बन सेक्टर प्रोग्राम लोन के

[†] The question was actually asked on the floor of the house by Dr. Ratnakar Pandey

लिये 250 मिलियन डालर है। अगले वर्षों के लिये जब हमारे वित्त मंत्री जी डा॰ मनमोहन सिंह जी वहां गये थे तो उनका वहां के अध्यक्ष से वार्तालाप हुआ था। अगले वर्ष के लिये, 1992-93 के लिये सात योजनायें है जिनकी चर्चा एशियन डेवलपमेंट बैंक से चल रही है और जो वार्तालाप की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। संभावना है कि ये चीजें हमें प्राप्त होगी। यह निश्चित हो चुका है कि पावर फाइनेंस कारपोरेशन के लिये 250 मिलियन डालर मिलेंगे। दूसरे प्रोजक्ट, पोर्ट्स डेवलपमेंट प्रोजक्ट सेंकड के लिये 150 मिलियन डालर, पावर प्रोजेक्ट दो नंबर के लिये 200 मिलियन डालर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक आफ इंडिया को 50 मिलियन डालर रोड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए 250 मिलियन डालर रेलवे थर्ड के लिए 200 मिलियन डालर और इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया को 150 मिलियन डालर। इसी प्रकार अगले वर्ष की योजनायें हैं। इसमें कोई खास ऐसी शर्तें नहीं हैं, जो शर्तें सामान्य होती है, जो कर्जा लेने में एक कर्जदार कंट्री दूसरे देश का देता है, वहीं शर्तें हमारे सामने है, कोई विशेष शर्त नहीं है जो कि राष्ट्रीय हित में न हो या देश के किसी प्रकार के विकास में सुविधापूर्वक न हो, ऐसी कोई भी शर्त हमें स्वीकार नहीं है और ऐसी कोई शर्त हमारे सामने नहीं है।

डा॰ रत्नाकर पाण्डेय: माननीय सभापति जी, क्या यह सही है कि वर्ल्ड बैंक तथा आई॰एम॰एफ॰ ने भारत सरकार को चेतावनी दी थी कि अवमूल्यन के कारण तथा अन्य वित्तीय कठिनाईयों को देखते हुए अगले दो-तीन वर्षों तक भारतीय अर्थ व्यवस्था को निर्यात में कमी तथा हार्ड करेंसी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और ऐसी स्थिति से उबरने के लिये भारत को विदेशी ऋण की व्यवस्था करनी चाहिये। यदि मेरे प्रश्न का उत्तर "हां" में है तो इस बारे में सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाये हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आई॰एम॰एफ॰ ने भारत सरकार को वित्तीय सुधार के लिये कुछ सुझाव दिये हैं, जिनको मानने के बाद भी आई॰एम॰एफ॰ से आगे सहायता प्राप्त हो सकती है। क्या कोई ऐसी शर्त है यह मैं जानना चाहता हूं?

श्री रामेश्वर ठाकुर: हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कल ही एक वक्तव्य सदन के सामने रखा है। उसमें विश्व बैंक और दूसरी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से जो हमारे लेन-देन की अवस्था है और जो शर्तें विश्व बैंक के साथ रखी गयी है, वह आपके सामने रखा गया है, यह उस वक्तव्य में आ चुका है। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। आप उसको देखें और अगर आप उसको गहराई से पढ़ेंगे तो पायेंगे कि वही सामान्य शर्तें है जो वित्तीय संस्थायें रखती हैं। हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, उसमें सुधार के लिये स्वयं सरकार निरंतर प्रयत्नशील है और इस संबंध में प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं, जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिले, आर्थिक स्थिति में सुधार हो और निर्यात में वृद्धि हो और हमारा जो विदेशी मुद्रा का कोष है, जो अब 8 हजार करोड़ रुपये से अधिक बढ़ चुका है वह और अधिक बढ़ सके (**व्यवधान**) आपने जो प्रश्न पूछा है वह मुख्य रूप से एशियन डवलपमेंट बैंक के बारे में हैं। चूंकि आपने अभी विश्व बैंक की चर्चा की है और हम समझते हैं कि चालू वर्ष में विश्व बैंक ने जो ऋण की स्वीकृति दी है वह शर्त सहित नहीं है और आगे के लिए एशियन डवलपमेंट बैंक से जो ऋण मिलने की सम्भावना है उसको प्राप्त करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। हमें जो आवश्यकता अपने देश के लिए होगी खास तौर से आठवीं योजना के परिप्रेक्ष्य में वह धन हमें बाहर से प्राप्त हो सकेगा। लेकिन हम सदन में कहना चाहते हैं कि आठवीं योजना में जो लागत होगी उसका 90 प्रतिशत अपने देश से ही प्राप्त होगा और लगभग 10 प्रतिशत के अन्दर हम विदेश से फायदा लेंगे।

श्री बेकल "उत्साही": सभापति महोदय, मैं आपके तवस्सुत खास तौर से वज़ीरे खज़ाना को मुतावज्जेह करना चाहता हूं (**व्यवधान**)

شری بیکل اتساہی - سبھاپتی
مہودے - میں آپکے توسط خاص طور
سے وزیر خزانہ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں
... مداخلت

श्री सभापति: वह मुतावज्जेह हैं (**व्यवधान**) उनकी तवज्जोह दोनों तरफ है मिनिस्टर आॅफ स्टेट की तरफ भी और आपकी तरफ भी है (**व्यवधान**)

श्री बेकल "उत्साही": उन्होंने बड़े विस्तार से, वित्त मंत्री (बैंकिंग) ने बड़े विस्तार से और तसल्ली के साथ जवाब दिया। मगर—

> रात भर पी उधार साक़ी से
> सुबह तक लाजवाब गुज़री है।
> मोहतसिब को हिसाब क्या देना
> ज़िन्दगी बेहिसाब गुज़री है।

सभापति महोदय, अर्थव्यवस्था को संकट से उभारने के लिए विदेशी कर्ज पर, एशियन डवलपमेंट बैंक पर कम से कम निर्भर होने की दिशा में भारतीय सरकार घरेलू खर्चों में कमी करने, बीमार इकाइयों को जिसमें करोड़ों रुपये लगे हुए हैं और लगातार घाटे में चल रही हैं, उन्हें बन्द करने तथा प्रवासी भारतीयों को अपनी पूंजी भारत में लगाने तथा बैंकों में जमा करने हेतु उत्साहित

करने के बारे में क्या प्रभावशाली कदम उठा रही है और इनके क्या नतायज़ निकलने की आशा है।

बहुत हसीन महाजन से राबिता रखना
मगर ज़माना हिसाबो किताब ले लेगा।

شری بیکل اتساہی: انہوں نے بڑے وستار سے وت منتری "بینکنگ" کے بڑے وستار سے اور تسلی کے ساتھ جواب دیا۔ مگر۔

رات بھر پی ادھار ساقی سے
صبح تک کا جواب گزری ہے
محتسب کو حساب کیا دینا
زندگی بے حساب گزری ہے

…. مداخلت …

سبھاپتی مہودے ارتھ ویوستھا کو سنکٹ سے ابھارنے کے لئے ودیشی قرض پر ایشین ڈولپمنٹ بینک پر کم سے کم نربھر ہونے کی دشا میں بھارت سرکار گھریلو خرچوں میں کمی کرنے بیمار ادیوگوں کو جس میں کروڑوں روپیئے لگے ہوئے ہیں اور لگاتار گھاٹے میں چل رہی ہیں انہیں بند کرنے تتھا ننھا پرواسی بھارتیوں کو اپنی پونجی بھارت میں لگانے تتھا بینکوں میں جمع کرنے ہیتو پروتساہن کرنے کے بارے میں کیا پربھاوشالی قدم اٹھا رہی ہے اور انکے کیا نتائج نکلنے کی آشا ہے

بہت حسین مہاجن سے رابطہ رکھنا
مگر زمانہ حساب و کتاب لے لیگا

श्री अजीत जोगी: इसका जवाब भी शेर में होना चाहिये (व्यवधान) जवाब में भी शेर कहिये (व्यवधान) एक नहीं दो शेर कहिये (व्यवधान)

SHRI T.R. BALU: The Minister should also reply in poetry, Sir.

डा॰ रत्नाकर पाण्डेय: शिव शंकर जी से पूछ लीजिये। बता देंगे।

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी: मैं आपको एक ही जुमले में जवाब दे दूं—

समझ सको तो खमोशी मेरा जवाब भी है।

مولانا عبیداللہ خان اعظمی … میں آپکو ایک ہی جملے میں جواب دے دوں

"سمجھ سکو تو خاموشی میرا جواب بھی ہے"

डा॰ रत्नाकर पाण्डेय: दम नहीं है। (व्यवधान)

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी: जनता बेंच वाला कांग्रेस के बेंच में नहीं जमता (व्यवधान)

مولانا عبیداللہ خان اعظمی - جنتا بینچ والا کانگریس کے بینچ میں نہیں جمتا

"مداخلت"

डा॰ रत्नाकर पाण्डेय: आपकी शायरी में दम नहीं था।

श्री सभापति: शायरी का मुकाबला नहीं हो रहा है।

श्री रामेश्वर ठाकुर: सभापति जी, वह समय निकल गया है जब ऋणम् कृत्वा घृतम् पीवेत अर्थात् ऋण ले कर घी पीएं। वह समय आज नहीं है। आप जानते हैं हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जो स्थिति पिछले दो सालों में हो गई थी वह हम सभी लोग जानते हैं। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार की यह बिलकुल कोशिश है कि सरकारी मद के खर्च में कमी की जाए और आर्थिक आमदनी का ज़रिया बढ़ाया जाए। इस दिशा में हमें कुछ सफलता भी मिली है। आय कर में वृद्धि हुई है। सीमा शुल्क आय में भी थोड़ी वृद्धि हुई है। हम प्रयत्नशील, हैं कि इसमें और भी वृद्धि हो, उद्योगों में वृद्धि हो, विदेशी व्यापार में भी वृद्धि हो, विदेशी मुद्रा की स्थिति और सुधर जाए। यह सारे प्रयास सरकार के चल रहे हैं। जहां तक बीमार इकाइयों का प्रश्न है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसे उद्योग हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है सरकार ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे चाहे सरकारी क्षेत्र में हों या गैर सरकारी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में हों, यह नितांत आवश्यक है कि किसी भी प्रतिष्ठान की क्षमता का उपयोग, उसकी उत्पादकता विशेषतः जो क्षमता की है, इफीशियंसी की है और उनका जो प्राफिट है वह बढ़ना चाहिए। उसी के आधार पर ये चल सकेंगे, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हों, यदि उनका उत्पादन ठीक नहीं होगा, व्यवस्था ठीक नहीं होगी और मुनाफा नहीं होगा तो अधिक दिनों तक नहीं चल सकेंगी। यह चलाने की बात नहीं है, चलने कीबात है। उसकी सुव्यवस्था की बात है जिसकी तरफ सरकार प्रयत्नशील है।

जहां तक भारत के मूल निवास के लोग विदेशों में हैं, हमने स्वयं अभी जो नयी योजनाएं बनाई है उनके आधार वे भारत में निवेश कर रहे हैं। उनका बहुत अच्छा हमें सहयोग मिला है, मिल रहा है और इस वक्त दोनों जो योजनाएं हैं, बाहर से विदेशी मुद्रा लाने की, फारेन रेमिटेंसेज की और जो भारत के विकास बांड की योजना है, दोनों में हमारे भारत के निवास के बाहर जो लोग रहते हैं जिनमें व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, दूसरे विशेषज्ञ हैं, डाक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लायर्स है, सभी लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं। भारत के प्रति उनकी निष्ठा बनी है, यहां की आर्थिक व्यवस्था में बनी है। इसमें सहयोग दे रहे हैं। हमें रुपया प्राप्त हो रहा है, और अधिक मिलने की भी आशा है। इसलिए 31 जनवरी तक हमने यह समय बढ़ाया है...(व्यवधान)

SHRI SURESH KALMADI: We have followed it, Sir.

SHRI KAMAL MORARKA: We have understood it, Sir.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: श्रीमान, जवाब ऐसा है...(व्यवधान)

"इस बात का डर है, इसलिए बेहिसाब पीता हूं"

सभापति: आपने भी कविता शुरू कर दी।

डा॰ रत्नाकर पाण्डेय: पहले कुछ करके फिर मिनिस्टर साहब इस तरह का जवाब दे रहे हैं। आपने जिस सरकार को समर्थन दिया उसने देश को दिवालिया बना दिया, बैंक्रप्ट बना दिया। उसके बाद भी खड़े होते हैं और प्रश्न पूछते हैं।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to ask the hon. Minister a very simple question. He has just now mentioned that seven schemes have been suggested for the next year by the ADB. I would like to know

whether we had asked for more schemes or we ourselves had asked for seven schemes only. How many schemes have we asked for, and how many have been sanctioned and are expected to be sanctioned? What is the total value of all these schemes we desired and that of those sanctioned for the next year? Are the regulations or the conditions same like those of the World Bank, or are they entirely different as far as the Asian Development Bank is concerned?

SHRI RAMESHWAR THAKUR: The Asian Development Bank's main areas of loans are development finance institutions, power generation sector, development of national and State highways, ports, high freight/railway routes and telecommunications. I have already given the details of the various schemes for the next year which were under discussion, in pipeline for the next year. Up to September, 1991 the disbursements have amounted to $712.4 million, that is, 29.1 per cent of the commitments. The Government has also cancelled a portion of one loan for ports' development amounting to $16.9 million. There have been substantial delays in the implementation of the North Madras Thermal Project, the Railway Modernisation Project and the Uchahar Thermal Extension Project. Therefore we have not been able to fully utilise it, and they have not yet released all the funds. Efforts are being made to implement all the projects.

As I have mentioned, there are seven projects which are in the pipeline for the next year 1992-93. They are under discussion. After the completion of the discussions, we are hopeful of getting those projects sanctioned. The ADB conditions are similar to the World Bank conditions. There are no extraordinary conditions. They are normal conditions.

श्रीमती सरला माहेश्वरी: माननीय सभापति जी, कहावत है कि हाथी के दांत दिखाने के और तथा खाने के और।...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप सवाल कर लीजिए। अब यह शायरी-कविता होने लगेगी, तो मुश्किल हो जाएगा।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: लेकिन माननीय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि हमारे..(व्यवधान)

SHRI A.G. KULKARNI: Because of television, everybody is interested in *Shayari* and *Kavita*.

श्री सभापति: वह तो बढ़िया बोल रही है।

SHRI G. SWAMINATHAN: Because of television the time consumed on question and answer has increased. Till now only two questions have been asked. Members who ask questions and those who reply take more time. Because of that the number of questions being taken up during the Question Hour is becoming less.

MR. CHAIRMAN: I agree with you.

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापतिजी, मेरा समय लिया जा रहा है।...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप जल्दी प्रश्न कीजिए। हाथी को छोड़ कर सवाल कीजिए।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने बड़े भोलेपन से कहा कि हमारे राष्ट्र पर कोई ऐसी शर्तें थोपी नहीं जा रही है, जो हमारे राष्ट्र के विरोधी हों, जबकि हकीकत यह है कि चाहे ए॰डी॰बी॰ हो, या विश्व बैंक हो, या एड इंडिया कन्सार्टियम हो या आई॰एम॰एफ॰ हो, इन तमाम संस्थाओं का इतिहास यह है कि यह विकासशील राष्ट्रों पर वाणिज्यिक शर्तें थोपने की एजेन्सी के रूप में काम करती रही है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि इन विशाल दैत्यों की सेवा में यह जो हमारे देश को सौंप रहे हैं, क्या उससे पहले मंत्री महोदय यह जरूरी नहीं समझते कि हमारे देश की जनता को और इस संसद को वे विश्वास में लेते, इस पर बहस करते और फाइनेंशल एडजस्टमेंट के नाम पर, वित्तीय समायोजन के नाम पर यह जो तमाम कदम उठाये जा रहे हैं, क्या वह इस बात से सहमत हैं कि यह जो कदम उठा रहे हैं, यह कदम हमारे राष्ट्र को अब तक की चली जा रही स्वतंत्र नीति के अनुकूल है?

जाहिर है कि वह ऐसा नहीं कह सकते। वह हमारी स्वतंत्र नीति के अनुकूल नहीं है, क्योंकि अब तक...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप प्रश्न कीजिए ना।

श्रीमती सरला माहेश्वरी: मैं प्रश्न पर ही आ रही हूं। बहुत परिवर्तन हो चुके हैं, सभापति जी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या यह जो वित्तीय समायोजन कर रहे हैं और बड़े-बड़े आर्थिक कदम उठा रहे हैं, जिसकी बड़ी सी भूमिका रत्नाकर जी ने रखी, मंत्री महोदय अपनी आर्थिक दशा और दिशा के बारे में संसद में कोई श्वेत-पत्र प्रस्तुत करने को तैयार है, या नहीं?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI MANMOHAN SINGH): I wish to assure this House that whatever agreements we are making with the international financial institutions, they are within the parameters and framework approved by this House. I have only yesterday placed on the Table of this hon. House a copy of the letter of intent that I gave to the International Monetary Fund. Hon. members can see from this that it is essentially a restatement of the policies which were outlined in the Budget, which were outlined in the industrial policy and the trade policy. All these have been discussed on the floor of the House. Therefore, there is no basis for the conclusion that any of these are inconsistent with our basic national interest.

SHRI VIREN J. SHAH: There are a large number of international financial organisations from whom we borrow—the World Bank, the IMF, ADB and IDA. Is there any coordination on our side and for what kind of different projects are we getting aid? Is there a coordination or combined action on behalf of these organisations, including the ADB and the Workd Bank? If so, is it in our interest or is it hurtful to us?

SHRI MANMOHAN SINGH: There is an Aid India Consortium, which meets every year and takes a total view of India's requirements for external resources. All the international financial institutions and donors are present. This is an annual event out of which emerges a total assessment of India's foreign exchange needs. This system has been in operation since 1958. It has, on the whole, enabled us to project our view much more coherently than would have been the case otherwise.

SHRI VIREN J. SHAH: Are ADB loans a part of that?

SHRI MANMOHAN SINGH: Yes.

Implementation of a National Project on Biogas Development

*363. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether Government are implementing a National Project on Biogas Development since 1981-82;

(b) if so, what achievements have been made in Orissa (districtwise) so far; and

(c) what are the names of the places where Regional Biogas Development Centres have been set-up so far and by when such a Centre would be set up in Orissa?

विद्युत और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में

(क) जी हां।

(ख) उड़ीसा राज्य में 1981-82 से 1990-91 के दौरान राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना के अंतर्गत स्थापित पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों की जिलावार संख्या इस प्रकार है:— बालासोर— 2565, बोलंगीर— 3747, कटक— 8008, धेनकानाल— 1762, गंजाम— 11928, कालाहांडी— 7300, कोंझार— 2737, कोरापुर— 3017, मयूरभंज— 6083, फूलबनी— 684, पुरी— 2742, सम्बलपुर— 7337 और सुन्दरगढ़— 3519 संयंत्र।

(ग) उड़ीसा राज्य में भुवनेश्वर में एक क्षेत्रीय बायोगैस विकास तथा प्रशिक्षण केन्द्र ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। उन 12 अन्य स्थानों के नाम जहां क्षेत्रीय बायोगैस विकास प्रशिक्षण स्थापित किए गए हैं वे हैं— उदयपुर (राजस्थान), कोयम्बटूर (तमिलनाडु), पुसा-समस्तीपुर (बिहार), इन्दौर (म.प्र.), पालमपुर (हिमाचल प्रदेश), खड़गपुर (पश्चिम बंगाल), गाजीपुर (उत्तर प्रदेश), हैदराबाद (आन्ध्र